



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 जनवरी, 2005/4 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जनवरी, 2005

संख्या एल०एल०आर०डी० (6)-25/2004-सेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-1-2005 को अनुमोदित हिमाचल

प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

2005 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2004

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23-1-2005 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 26 अक्टूबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1968 का 8

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 42 का प्रतिस्थापन।

“42. फीसों में वृद्धि करने, कमी करने, परिहार करने या प्रतिदाय करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित या अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त फीसों में या उनमें से किसी में वृद्धि कर सकेगी, कमी कर सकेगी, परिहार कर सकेगी या प्रतिदाय कर सकेगी; या अन्यथा तथाकथित अनुसूचियों में संशोधन कर सकेगी और उसी रीति में ऐसी अधिसूचना को विखण्डित या संशोधित कर सकेगी।”।

3. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

2004 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT)
ACT, 2004

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD JANUARY, 2005)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of October, 2004.

Substitution
of section 42.

2. For section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following shall be substituted, namely :—

8 of 1968

“42. *Power to enhance, reduce, remit or refund fees.*—The State Government may, by notification in the Official Gazette, enhance, reduce, remit or refund, all or any of the fees provided in this Act or specified in the First and Second Schedules appended to the Act; or otherwise amend the said Schedules and may in the like manner rescind or amend such notification.”

Repeal of
Ordinance
No. 4 of 2004
and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.